समक्ष : *ए. एल. बहरी और* अशोक *खान,*
न्यायमूर्ति

पूनम यादव,-याचिकाकर्ता,

बनाम

श्री चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और *अन्य,-उत्तरदाता।*

***1992 की सिविल रिट* याचिका संख्या 11775।**

16 सितंबर, 1992।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227-प्रवेश-पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की मांग करने वाला याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 4 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाला जिसने अतिरिक्त सीट बनाए जाने के बाद अनुकंपा के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया-याचिकाकर्ता को प्रवेश से इनकार करने वाली विश्वविद्यालय की कार्रवाई को चुनौती दी गई-यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालय की कार्रवाई अतिरिक्त सीट बनाने में मनमाना है।

*ये अभिनिर्धारित किया गया- विश्वविद्यालय की कार्रवाई मनमाना है। प्रतिवादी संख्या 4 के लिए एक विशेष सीट का सृजन, जिसने प्रवेश के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय है जो इसे मनमानेपन के दायरे में लाता है। इससे यह निहित नहीं होना चाहिए कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय एक विशेष सीट **नहीं** बना सका। एक*

न्यायोचित कारण के लिए विशेष सीट बनाई जा सकती है, जो हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में मौजूद नहीं थी।
(अनुच्छेद 4)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि, विश्वविद्यालय में प्रवेश बड़े पैमाने पर समाज के हितों के लिए है और केवल प्रतिवादी संख्या 4 जैसे अनुकंपा के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से जब उसने पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी।

(अनुच्छेद 6)

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता एन. एस. पंवार,*

सुमंत बत्रा, अधिवक्ता, *विश्वविद्यालय के लिए।*

रवि वर्मा, अधिवक्ता, *प्रतिवादी की ओर से।*

निर्णय

*ए. एल. बहरी,*न्यायमूर्ति

.

(1) याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को आदेश पत्र या किसी अन्य उपयुक्त *रिट* को जारी करने के लिए दायर किया है, या प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक (संक्षेप में बी.वी.एससी. और ए.एच.) में प्रवेश देने का निर्देश देने के लिए दायर की है। आरक्षित सीटों की संख्या सहित कुल सीटों की संख्या 50 थी। 24 सीटें सामान्य श्रेणी के के अभ्यर्थियों लिए थीं । याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी है। पक्षों का यह मामला स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 24 सीटों के संबंध में योग्यता के आधार पर नहीं आया था। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि प्रतिवादी संख्या 4 श्री अभिषेक ढिंसा को पाठ्यक्रम में भर्ती कराया गया है, हालांकि वह योग्यता में बहुत कम थे। याचिकाकर्ता को वेटेज सहित प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा प्राप्त 71 प्रतिशत अंकों की तुलना में 83.33 प्रतिशत

अंक मिले।सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में से अंतिम अंतिम अभ्यर्थी 87.33 प्रतिशत अंकों के साथ भर्ती हुआ था।

(2) विश्वविद्यालय के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं। प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयानों में लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित **पहली** 24 सीटों में पद हासिल करने में विफल रहे। वास्तव में, अभी भी 20 छात्र थे जो सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों के लिए याचिकाकर्ता की तुलना में योग्यता में अधिक थे, कि प्रतिवादी **संख्या 4** को प्रतिवादी संख्या 4 के पिता द्वारा किए गए आवेदन पर अनुकंपा के आधार पर एक अतिरिक्त सीट बनाकर प्रवेश दिया गया है। उल्लिखित अनुकंपा का आधार यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 की माँ की मृत्यु उस अवधि के दौरान हुई जब वह अपनी परीक्षा दे रहा था और यही कारण है कि वह योग्यता के आधार पर भर्ती होने के लिए पर्याप्त संख्या में अंक प्राप्त नहीं कर सका। इसे एक सीट बनाने के लिए एक आधार मानते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई गई थी जिसे उक्त सीट के खिलाफ भर्ती किया गया था।

[(3)] हमने पार्टियों के वकील सुना है। यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों के साथ किया था । वह योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। उनके लिए विशेष सीट बनाई गई थी, जिससे पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के लिए तैयार की गई योग्यता सूची को अनदेख किया गया था । प्रत्यर्थियों के वकील ने तर्क दिया कि रिट याचिका में

ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 को दिए गए प्रवेश को रद्द करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जाए। हम इस प्रस्तुति में कोई सार नहीं पाते है । इस विशिष्ट प्रार्थना के अलावा कि उसे भर्ती किया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में यह भी प्रार्थना की है कि अदालत द्वारा जारी कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश उचित ~~समझे।~~ चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 ने पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा की है, इसलिए इन परिस्थितियों में, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उसके लिए एक विशेष सीट का निर्माण, पूरी तरह से अनावश्यक है । हमारी राय में, विश्वविद्यालय की कार्रवाई मनमाना ~~है।~~ प्रतिवादी संख्या 4 के लिए एक विशेष सीट का सृजन, जिसने प्रवेश के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मनमानेपन के दायरे में लाना अवांछनीय ~~है।~~ इससे यह निहित नहीं होना चाहिए कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय एक विशेष सीट नहीं बना सका। विशेष सीट एक न्यायोचित कारण के लिए बनाई जा सकती है जो हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में मौजूद नहीं था।हम खुद को उन विशेष परिस्थितियों की गणना करने से बचाते हैं जिनके तहत एक सीट बनाई जा ~~सकती है।~~ ।आम तौर पर, योग्यता के आधार पर भरी गई सीटों को कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

(3)[(4)] इसके बाद प्रत्यर्थियों के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता केवल 50 सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिसके लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और न कि 51 वीं सीटों के खिलाफ, जो विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के लिए बनाया गया था क्योंकि क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं

था। याचिकाकर्ता या किसी अन्य समान रूप से **स्थित व्यक्ति का** कोई अधिकार किसी भी तरह से *प्रतिकूल रूप* से *प्रभावित नहीं हुआ था। एस. एस.* सोधी, जे. ने परवीन हंस बनाम पंजीयक, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (1) में अपने समक्ष उठाई गई याचिका को खारिज करते हुए कहा: —

> "इस स्थिति का सामना करते हुए, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जवाहर लाल गुप्ता, ने यह तर्क देने की मांग की कि चूंकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के पक्ष में यह आरक्षण नव निर्मित सीटों के खिलाफ किया गया था, **इसलिए इसके तहत प्रवेश का दावा करने वाले व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है।**

(1) 1990 (1) आर. एस. जे. 405

अन्य श्रेणियों पर किसी **भी तरह** से **प्रतिकूल** प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इस आरक्षण को इस दलील पर उचित ठहराने का प्रयास किया गया कि यह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कल्याण के उपाय के रूप में किया गया था। उन्होंने इस संबंध में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आंदोलन की भी चेतावनी दी। उनके तर्क को विश्वास दिलाने के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए इस तरह के आरक्षण की तुलना भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को दिए जा रहे रेलवे पास से करने का भी प्रयास किया गया था।यह वास्तव में एक पूरी तरह से असमर्थनीय रुख है।विश्वविद्यालय में प्रवेश बड़े पैमाने पर समाज के लिए होते हैं और जो आरक्षण किए जाते हैं, वे उस नुकसान या बाधा के लिए भत्ते बनाने के लिए बनाए जाते हैं जिससे एक विशेष श्रेणी पीड़ित हो सकती है।वे केवल कल्याण के उपाय के रूप में दिए जाने के लिए नहीं थे। इसलिए रेलवे कर्मचारियों को दिए जा रहे रेलवे पास की तुलना जांच के दायरे में नहीं आ सकती है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन का संदर्भ विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के पाठ्यक्रम के आगे झुकने को उचित नहीं ठहरा सकता है, जो स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है।जैसा कि बाध्यकारी न्यायिक पूर्व निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, आरक्षण, जिन्हें पहले संदर्भित किया गया है, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं रखते हैं और स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण

हैं और इस प्रकार उन्हें पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाना चाहिए।"

हम एस. एस. सोधी, जे. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि विश्वविद्यालय में प्रवेश बड़े पैमाने पर समाज के लिए है और केवल अनुकंपा **के आधार पर नहीं दिया जा सकता** है, जैसे प्रतिवादी संख्या 4, विशेष रूप से जब उन्होंने पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। प्रतिवादी संख्या 4 के वकील ने तर्क दिया कि उनके लिए निर्धारित सीट को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हम इस प्रस्तुति में कोई सार नहीं पाते हैं। पाठ्यक्रम में अध्ययन अब तक शुरू हो चुका है और हमारी राय में प्रतिवादी संख्या 4 में कोई विशेष समानता निहित नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 4 की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है।हम निर्देश देते हैं कि जो अतिरिक्त सीट बनाई गई है, वह उस छात्र को दी जाए जिसने योग्यता के आदेश में आवेदन किया था, यदि विश्वविद्यालय बनाई गई अतिरिक्त सीट को बनाए रखना चाहता है। विश्वविद्यालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह नव निर्मित सीट को न **भरे क्योंकि यह विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के लिए बनाया गया था। कोई लागत नहीं।**

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में

इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी,
गुरुग्राम,
हरियाणा ।